Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.471
Volume - 6, Issue - 5, May - 2023 Publication Date: 31/05/2023

DOIs:10.2018/SS/202305005 --:-- Research Paper / Article / Review

बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत की नई शिक्षा नीति का मूल्यांकन

डॉ. शिवराम सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र, डी.एस.एम. डिग्री कॉलेज, काँठ मुरादाबाद - 244501
Email - shivrambanasthali@gmail

सार : भारत देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू हो गई हैं। जिसने 1986 की शिक्षा नीति का स्थान लिया है। इस नई शिक्षा नीति को धीरे-धीरे योजनाबद्ध तरीके से विस्तारित किया जा रहा है। वर्ष 2021 में ई-लर्निंग को और भी ज्यादा प्राथमिकता देते हुए नए संकल्प सरकार द्वारा लिये गये। नवाचार के माध्यम से डिजिटल शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया। भारत की प्राचीन संस्कृति और मूल्यों को नए क्लेवर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही शिक्षा को वैश्विक पहचान सुलभ करायी जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति वैश्विक समाकलन का कार्य करेगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति **2020** में कक्षा-**5** तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन का माध्यम अपनाने की बात कही गई। कक्षा-**8** में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात है। उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प होगा**,** किंतु भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न को शामिल किया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से अपेक्षित है कि यह उच्च संस्थानों की समस्याओं के समाधान पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को रुपांतरित कर देगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी। **1986** के बाद आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि करना है।

बीज शब्द : राष्ट्रीय शिक्षा नीति**,** नवाचार डिजिटल**,** वैश्विक**,** गुणवत्तापूर्ण।

1. परिचय :

शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है - सीखने एवं सिखाने की क्रिया किन्तु व्यापक अर्थ में शिक्षा किसी भी समाज में निरन्तर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। शिक्षा के सम्बन्ध में गाँधीजी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानन्द का कहना था कि मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है।

नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति की कमियाँ दूर करने का कार्य करेगी। नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही 'मानव संसाधन मंत्रालय' का नाम बदलकर 'शिक्षा मंत्रालय' कर दिया गया। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत् 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100 प्रतिशत GER के साथ शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कक्षा - 5 तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन का माध्यम अपनाने की बात कही गयी। कक्षा - 8 में मातृभाषा को प्राथमिकता देने की बात है। उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प होगा, किन्तु भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी। छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सेमेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्नों को शामिल किया जायेगा।

2. सुशिक्षित समाज की दिशा में गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की डिजिटल कदम :

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के स्कूली बच्चों से लेकर विश्वविद्यालय के छात्रों के न केवल पढ़ाई के तरीके बदलेंगे बल्कि उनकी परीक्षा के मूल्यांकन में भी बदलाव दिखेगा। आरटीई के दायरे में अब 3-18 साल के बच्चों को

शामिल किया जायेगा। स्कूलों के सिलेबस में बदलाव किया जायेगा। देश में ऐसे क्षेत्र/भाग जहाँ व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्ति की उपलब्धता संभव नहीं हैं, वहाँ डिजिटल अबसंरचना डिजिटल कंटेट से ई-शिक्षा उपलब्ध करायी जायेंगी।

3. राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उच्च शिक्षा :

वर्तमान में 1000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थान देश में मौजूद हैं, जिनमें राष्ट्रीय महत्व के 150 से अधिक संस्थान भी शामिल है। उच्च शिक्षा संस्थानों के पिछले दशक में शोधों की संख्या और उनकी गुणवत्ता दोनों में ही लगातार वृद्धि प्रदर्शित की है। वर्तमान में भारत कुल शोध प्रकाशनों के मामले में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है और कुछ शोध प्रकाशनों में इसकी हिस्सेदारी 5.31 प्रतिशत है। शिक्षा, ज्ञान सृजन और नवाचार इन तीन पहलुओं में से पहले दो पहलूओं में भारत उच्च शिक्षण संस्थानों ने सापेक्षिक रूप से बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हैं, लेकिन नवाचार के मामले में पीछे रहे हैं।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा में मल्टीपल एंट्री एंड एक्जिट सिस्टम भी देखने को मिलेगा, जिनमें विद्यार्थियों को एक साल की पढ़ाई करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा और दो साल की पढ़ाई करने पर डिप्लोमा तथा कोर्स पूरा करने पर डिग्री मिलेंगी और भविष्य में प्रवेश लेने के लिए ये रिकार्ड भी क्रेडिट ट्रांसफर के जरिए उपयोग में आऐंगे। जो छात्र रिसर्च में जाना चाहते हैं वह एक साल के एम.ए. के साथ चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से यह अपेक्षित है कि यह उच्च संस्थानों को 'समरूपता की तलाश में समाधान' के बजाय 'समस्याओं के समाधान' पर कार्य करने के लिए प्रेरित कर भारत में उच्च शिक्षा के परिदृश्य को रूपांतरित कर देगा।

4. पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों ?

· बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

· शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

· भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिए शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।

भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों की समस्याएँ -

· विद्यालय स्तर पर नामांकन में वृद्धि के साथ उच्च शिक्षा संस्थानों की आपूर्ति देश में शिक्षा की बढ़ती माँग को पूरा करने में अपर्याप्त है।

· भारत में बड़ी संख्या में कॉलेज और विश्वविद्यालय यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित न्यूनतम शर्तो को पूरा करने में असमर्थ है।

· भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए बदतर बुनियादी ढ़ाँचा विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थानों में अवसंरचना तथा भौतिक सुविधाओं की स्थिति अच्छी नहीं है।

· भारतीय शिक्षा प्रबंधन अति-केन्द्रीकरण, नौकरशाही संरचनाओं और उत्तरदायित्व पारदर्शिता एवं व्यावसायिकता की चुनौतियों का सामना कर रहा है।

5. नई शिक्षा नीति के उद्देश्य :

· यह भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्च गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराकर और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी।

· इस नीति से छात्र अपने मौलिक दायित्व और संवैधानिक मूल्य देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका के उत्तरदायित्व की जागरूकता उत्पन्न करे।

· इस नीति का विजन है छात्रों में भारतीय होने का गर्व केवल विचार में ही नहीं बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी रहे, साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए।

· अच्छा प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

· प्रत्येक संस्थान में एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय स्थापित किया जायेगा।

6. नई शिक्षा नीति की उपयोगिता का मूल्यांकन :

· छात्रों के प्रगति को मूल्यांकन के लिए 'परख' (PARAKH) नामक राष्ट्रीय आंकलन केन्द्र की स्थापना की जायेगी।
· शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (National Professional Standards for Teachers-NPST) का विकास किया जायेगा।
· नई शिक्षा नीति में एम.फिल. कोर्स को समाप्त कर दिया गया।
· देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए एक एकल नियामक/भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (HECI) की परिकल्पना की गई है।
· आकांक्षी जिले (Aspirational District) जहाँ आर्थिक सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र है, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' के रूप में नामित किया जायेगा।
· केन्द्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने की दिशा में एक 'जेण्डर इन्क्लूजन फंड' की स्थापना करेगा।
· कला वर्ग और विज्ञान वर्ग के छात्रों में कोई अन्तर नहीं किया जायेगा। कला वर्ग का विद्यार्थी विज्ञान वर्ग के विषयों को भी पढ़ सकता है।
· सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा मानक समान रहेंगे।
· सम्पूर्ण देश के लिए एक सिलेबस लागू किया जायेगा।
· नई शिक्षा नीति को तेजी से बदलते समाज की जरूरतों के आधार पर तैयार किया गया है।
· बहु-विषयक विश्वविद्यालय शोधकर्त्ताओं की रचनात्मक क्षमता पर बल देगी।
· 2035 तक सकल नामांकन अनुपात के मौजूदा 27 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य प्राप्त करना है।
· उच्च शिक्षा के लिए पहली बार सरकार ने शिक्षा के मद में सकल घरेलू उत्पाद के 6 प्रतिशत के रूप में बजट आवंटन का वादा किया है।
· उच्च शिक्षा संस्थान 3-I (Interdiscipline Research, Industry Connect, and Internationalisation) पर ध्यान केन्द्रित करेंगी।

7. नई शिक्षा नीति से सम्बन्धित चुनौतियाँ -

· शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय होने के कारण राज्यों का सहयोग अपेक्षित।
· विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से शिक्षा मंहँगी होने की सम्भावना।
· 'त्रि-भाषा' से शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का आरोप।
· फंडिग सम्बन्धी जाँच का अपर्याप्त होना।
· मानव संसाधन का अभाव।
· योग्य शिक्षकों की अनुपलब्धता भी गुणवतापूर्ण शिक्षा के मार्ग में चुनौतियाँ खड़ी है।

8. निष्कर्ष :

केन्द्र सरकार ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई शिक्षा नीति को मंजूरी दी है, अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आयेंगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत् 3-18 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अन्तर्गत रखा गया है। 1986 के बाद आयी इस शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री डी मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों से कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करेगी।

सन्दर्भ सूची :

1. www. Drishti IAS, The Vision - 15 Nov. 2022

2. दैनिक समाचार पत्र 'दैनिक जागरण' 02 जनवरी 2021
3. दृष्टि आई.ए.एस. 'नई शिक्षा नीति 2020 25 अगस्त 2020
4. दैनिक समाचार पत्र, 'अमर उजाला' - 21 दिसम्बर 2021
5. www.bbc.Hindi.Com नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020
6. कुमार के. (2005), 21वीं सदी की शुरूआत में शिक्षा की गुणवत्ता
7. Puri, Natasha (30 August 2019) A Review of the National Education Policy of The Government of India.
8. www.mhrd.gov.in NEP Final English PDF - 10 August 2020.